

## पूरी बेंच

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधावालिया, माननीय न्यायमूर्ति श्री  
गुरनाम सिंह और माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.सी. मितल, के सामने

देई चंद फौगाट,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 231, 1979,

18 मार्च 1980

पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम, 1965, पंजाब सरकार द्वारा संशोधित राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) हरियाणा दूसरा संशोधन नियम 1976—नियम 2—भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 14, 16 और 309—सैन्य सेवा—डिफी-इसकी शर्तों को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया है - ऐसी सेवा का लाभ केवल उन लोगों तक ही सीमित है जो आपातकाल के दौरान शामिल हुए थे - ऐसा प्रतिबंध - क्या यह अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने वाला वर्गीकरण बनाता है - नियम - क्या पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया जा सकता है - पहले के लाभों को पूर्वव्यापी रूप से छीन लिया जा सकता है - क्या इनकार किया जा सकता है अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा गारंटीकृत समानता।

अभिनिर्धारित किया गया, (प्रति बहुमत माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एस. संधावालिया सी.जे. और माननीय न्यायमूर्ति श्री गुरनाम सिंह जे., माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.सी. मितल, जे., कॉन्ट्रा) कि संपूर्ण पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम, 1965 की योजना और निकाय की जांच, जैसा कि मूल रूप से 1965 में बनाया गया था। यह संकेत देगा कि ये स्पष्ट रूप से सरकार द्वारा उन लोगों को दी गई रियायत की प्रकृति में हैं जिन्होंने उसके विचार में आपातकाल के दौरान देश को सेवा प्रदान की थी। इन नियमों से पहले, सैन्य सेवा प्रदान करने वाले पुरुषों को वेतन वृद्धि, पेंशन, वरिष्ठता या पदोन्नति आदि से संबंधित कोई भी लाभ उपलब्ध नहीं था। ऐसा नहीं है कि जब भी कोई सैनिक नागरिक रोजगार में स्थानांतरित होता है तो इन लाभों का दावा करने के लिए उसके पास पहले से ही कोई मौलिक या अंतर्निहित अधिकार मौजूद था। राज्य ये लाभ किसी विशेष वर्ग को प्रदान कर सकता है और किसी अन्य वर्ग के बहिष्कार को न तो भेदभावपूर्ण माना जा सकता है और न ही निहित अधिकार छीनने वाला कहा जा सकता है। मूल रूप से राज्य ने प्रोत्साहन और पुरस्कार दोनों के रूप में सैन्य सेवा के लिए मान्यता के रूप में अपने इनाम में ये रियायतें या लाभ दिए थे और ऐसा लगता है कि मूल

रूप से रियायतें देने के समय, यह राज्य का काम है। उसके लाभार्थी का चयन करें और जहां इसे व्यक्तियों के एक बड़े समूह तक विस्तारित करने की मांग की जाती है, तभी शायद उनके एक पहचान योग्य वर्ग होने का विचार अच्छी तरह से उठ सकता है। जो व्यक्ति आपातकाल की घोषणा और उसके परिणामस्वरूप युद्ध के आसन्न खतरे के दौरान स्वेच्छा से नामांकन करने या कमीशन मांगने के लिए आगे आते हैं, वे स्वयं एक वर्ग बना लेंगे। यह स्वयंसिद्ध है कि युद्ध से उत्पन्न होने वाले घातक खतरे के सामने कई लोग इसके खतरों को उठाने से झिझकेंगे। जबकि शांति के समय में कई राज्यों में भर्ती करने वालों की कोई कमी नहीं होती, युद्ध के समय संबंधित व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध भी भर्ती या मर्दानगी का मसौदा तैयार करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए, सभी घातक खतरों के साथ युद्ध सेवा के लिए स्वेच्छा से काम करने वाले व्यक्तियों का वर्ग निस्संदेह सेवा कैरियरवादियों से अलग है। पिथिली, यह एक ऐसा वर्ग है जो युद्ध के समय हथियारों के आह्वान का देशभक्तिपूर्वक जवाब देता है, उन लोगों के खिलाफ जो समान रूप से सम्मानजनक भूमिका निभाते हैं लेकिन निस्संदेह उन लोगों से अलग हैं, जो आपातकाल के पेटेंट और कभी-कभी घातक खतरों का सामना करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति आपातकाल की घोषणा से पहले सेवा में शामिल हुए थे, वे स्पष्ट रूप से पेशेवर सैनिक और नियमित सेवा कैरियर के दायरे में आएं, उन लोगों के विपरीत जो युद्ध की स्थिति में आपातकाल के दौरान स्वेच्छा से भर्ती होने या कमीशन लेने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। अनुचित होने से दूर, यह वर्गीकरण वास्तव में सबसे स्वाभाविक प्रतीत होता है। (पैरा 13 और 14).

अभिनिर्धारित किया गया, (प्रति माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एस. संधावालिया, सी.जे., और माननीय न्यायमूर्ति श्री गुरनाम सिंह) कि राज्य के पास भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत, जब तक विधानमंडल अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में संबंध में एक अधिनियम नहीं बनाता, तब तक नियम बनाने की पूर्ण शक्ति है। किसी अधिनियम के अभाव में राज्य वस्तुतः विधायिका के स्थान पर आ जाता है और उसके पास पूर्वव्यापी रूप से नियम बनाने की पूर्ण शक्ति होती है। एक बार ऐसा होने पर, नियमों के उसी सेट में हरियाणा संशोधन द्वारा पंजाब नियमों द्वारा पहले दी गई रियायत को छीनना अनिवार्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन नहीं है। यह प्राथमिक प्रतीत होता है कि किसी भी कानून का पूर्वव्यापी प्रभाव अनिवार्य रूप से पहले से मौजूद अधिकारों को प्रभावित या परिवर्तित करना चाहिए। केवल इसलिए कि वे ऐसा करते हैं, पूर्वव्यापी कानून को समानता नियम का उल्लंघन करने वाला घोषित नहीं किया जा सकता है। ऐसा मानने का वास्तव में अर्थ यह होगा कि पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की कोई वैध शक्ति कभी नहीं हो सकती। इस प्रकार, यह माना जाना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियमों को पूर्वव्यापी रूप से

अधिनियमित करने की पूर्ण शक्ति रखने वाला राज्य अनिवार्य रूप से नियमों के एक ही सेट द्वारा पहले दी गई किसी भी रियायत को किसी भी तरह से संविधान के 14 और 16 अनुच्छेदों में निहित समानता नियम का उल्लंघन या उल्लंघन किए बिना वापस ले सकता है।  
(पैरा 8, 9 और 10)

अभिनिर्धारित किया गया (प्रति माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. सी. मित्तल, कॉन्ट्रा) कि हरियाणा द्वितीय संशोधन नियम, 1976, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है क्योंकि इसमें किया गया वर्गीकरण पूरी तरह से अनुचित और मनमाना है। चाहे मूल परिभाषा के अंतर्गत हो या संशोधित परिभाषा के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान सैन्य सेवा में व्यतीत की गई अवधि का लाभ दिया जाना है। यदि उद्घोषणा या आपातकाल के दौरान सैन्य सेवा का लाभ दिया जाना है, तो केवल उन लोगों को लाभ देने के लिए कोई सांठगांठ या आधार नहीं है जो आपातकाल के संचालन के दौरान नामांकित या कमीशन किए गए थे, उन्हें नहीं, जो पहले नामांकित या कमीशन किए गए थे। आपातकाल की उद्घोषणा, लेकिन उस अवधि या आपातकाल के दौरान कार्यान्वित। चाहे कोई व्यक्ति आपातकाल की घोषणा से पहले या उसके जारी रहने के दौरान सैन्य सेवा में शामिल हुआ हो, सभी सैन्य सेवा के समान जोखिमों के अधीन आपातकाल की घोषणा के दौरान समान रूप से देश की सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसलिए, हरियाणा नियमों में निहित सैन्य सेवा की परिभाषा मनमानी, अनुचित और भेदभावपूर्ण है, जिसका कोई संबंध नहीं है और जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है वह हासिल नहीं किया जा रहा है और यह स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।  
(पैरा 29, 30 और 34)

अभिनिर्धारित किया गया (माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.सी.मित्तल, कॉन्ट्रा के अनुसार) कि पंजाब नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए थे, जिसका लाभ हर उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने आपातकाल की घोषणा के दौरान सेना में सेवा की हो, यह अधिकार का मामला है। चूँकि एक बार वैधानिक नियम बन जाने के बाद उन्हें केवल रियायतें नहीं माना जाएगा, बल्कि वैधानिक नियमों के तहत बनाया गया एक अधिकार माना जाएगा, जिसे अदालत में लागू किया जा सकता है। इसलिए, इसके तहत दिया गया लाभ कोई रियायत नहीं बल्कि एक वैधानिक अधिकार था जिसे अदालत में लागू किया जा सकता था।  
(पैरा 32)

मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 8 अगस्त, 1979 को माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधावालिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति जी.सी. मित्तल द्वारा मामले को पूर्ण पीठ के पास भेजा गया। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधावालिया, माननीय श्री न्यायमूर्ति गुरनाम सिंह और माननीय श्री न्यायमूर्ति जी.सी. मित्तल की पूर्ण पीठ ने अंततः 18 मार्च, 1980 को मामले का फैसला किया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय मामले के रिकॉर्ड भेजने और उसका अवलोकन करने की कृपा करेगा: -

- (i) 15 जनवरी 1979 के आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी/4 को रद्द करते हुए सर्टिओरीरी की रिट जारी करें।
- (ii) उत्तरदाताओं को नियमों के नियम 4 से मिलने वाले सभी लाभों को याचिकाकर्ता को जारी करने का आदेश देते हुए एक परमादेश रिट जारी करें और याचिकाकर्ता को सहायक उत्पाद शुल्क के रूप में सेवा में शामिल होने की तारीख से उसी का हकदार घोषित करें। कराधान अधिकारी यानी 22 मई, 1973, जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार होता, यदि उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ आक्षेपित निर्णय अनुलग्नक पी/4 नहीं लिया गया होता।
- (iii) कोई अन्य राहत जो यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता के मामले में उचित समझे।
- (iv) उत्तरदाताओं को पूर्व नोटिस से मुक्ति दी जाए।
- (v) पी/एल से पी/7 तक के अनुलग्नों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की छूट दी जाए।
- (vi) याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जाए।

याचिकाकर्ता के वकील एस.एम.हुड्डा।

प्रतिवादी की ओर से यू.डी. गौड़ ए.जी. (हार्ड.) और बी.एल. गुलाटी।

आदेश

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधावालिया,

(1) क्या बहादुर स्वयंसेवक, जो युद्ध की स्थिति में स्वेच्छा से हथियारों के आह्वान का जवाब देते हैं, शांति के समय में करियर या रोजगार के रूप में सेवाओं को चुनने वाले

पुरुषों से अलग एक वर्ग बनाते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है एक संदर्भ पर जो इस पूर्ण पीठ के समक्ष निर्धारण के लिए आता है। मेरे विचार से, उत्तर स्पष्ट है - कि वे ऐसा करते हैं।

(2) मुझे अपने विद्वान भाई न्यायमूर्ति जी.सी. मित्तल, द्वारा दर्ज किए गए फैसले को पढ़ने का सौभाग्य मिला है, और यह काफी अफसोस और समान संदेह के साथ है कि मैं उस पर असहमति दर्ज करने के लिए मजबूर महसूस करता हूँ। अत्यंत सम्मान के साथ, यदि मैं ऐसा कह सकता हूँ, तो उपरोक्त केंद्रीय और मुख्य प्रश्न, जिसके उत्तर की आवश्यकता थी, सहायक और संपार्श्विक मुद्दों की परिधीय शब्दावली में फैल गया प्रतीत होता है और इसलिए, शायद परिणामी उत्तर आ गया है।

(3) मेरे विद्वान भाई न्यायमूर्ति जी.सी. मित्तल के फैसले में तथ्य काफी विस्तार से सामने आए हैं। फिर भी इस फैसले की एकरूपता बनाए रखने के लिए उनका कुछ संदर्भ अपरिहार्य हो जाता है, याचिकाकर्ता देई चंद 9 दिसंबर को भारतीय वायु सेना में शामिल हुए। 1960, आपातकाल की घोषणा से बहुत पहले एक नियमित योद्धा के रूप में और 1969 तक काफी समय तक सेवा की, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने 1970-71 में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और अन्य संबद्ध सेवाओं की एक खुली परीक्षा में भाग लिया और सैन्य जारी कर्मियों के लिए आरक्षित कोटा के तहत संबद्ध सेवाओं की सामान्य श्रेणी में चुना गया। वह 22 मई, 1973 को सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी के रूप में शामिल हुए, लेकिन 20 फरवरी, 1976 तक ऐसा नहीं हुआ, - अनुबंध पी. 2 के माध्यम से, हरियाणा के राज्यपाल ने आदेश दिया कि 30 सितंबर, 1975 से पूर्वव्यापी प्रभाव से संतोषजनक उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है। हालाँकि, यह मामला है कि 2 जनवरी, 1974 को पहले भी याचिकाकर्ता ने वैधानिक नियमों के तहत सैन्य सेवा लाभ देने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था, जिसका अस्तित्व उस समय लागू था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन नियमों के सही अनुप्रयोग ने सरकार के लिए काफी कठिनाइयाँ पैदा कीं और याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कुछ स्पष्टीकरणों के अभाव में लंबित रहा, जो प्रतिवादी-राज्य से मांगे गए थे। जैसा कि आगे बताया जाएगा, यह प्रश्न उच्च न्यायालय के समक्ष भी निर्णय के लिए लंबित था और 12 दिसंबर, 1975 को ही निर्णय सुनाया गया था। इसके बाद हरियाणा राज्य ने 4 अगस्त, 1976 को सैन्य सेवा की परिभाषा में एक संशोधन किया, जिससे इसे पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया। इस संशोधन के आवश्यक परिणाम के रूप में, याचिकाकर्ता को परिशिष्ट पी. 4, दिनांक 15 जनवरी, 1977 के माध्यम से सूचित किया गया था कि क्योंकि वह आपातकाल की अवधि के दौरान सेवा में नामांकित नहीं हुआ था, इसलिए, उसे नागरिक रोजगार में सैन्य सेवा का लाभ नहीं दिया जा सकता। अतः इस आधार पर उनका अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने उसे सैन्य सेवा का लाभ देने से

इनकार करने और नियमों में किए गए संशोधन की संवैधानिकता पर सवाल उठाने को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की है।

(4) विवाद में मुद्दे की सराहना करने के लिए वैधानिक नियमों के विधायी इतिहास पर संक्षेप में ध्यान देना उचित और वास्तव में आवश्यक है जिसके चारों ओर तर्क घूमता है। 20 जुलाई, 1965 को पंजाब के समग्र राज्य ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम, 1965 को प्रख्यापित किया था, ताकि कुछ प्रावधान किए जा सकें। नियम 2 में परिभाषित 'सैन्य सेवा' प्रदान करने वाले व्यक्तियों को वेतन वृद्धि, वरिष्ठता, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों के संबंध में रियायतें। उत्तरदाताओं का यह रुख था कि उपरोक्त परिभाषा की भाषा में कुछ अस्पष्टता के बावजूद, नियमों के निर्माताओं का इरादा और पंजाब के समग्र राज्य में और बाद में हरियाणा के उत्तराधिकारी राज्य में इसके बाद के आवेदन का प्रभाव था। सैन्य सेवा का लाभ केवल उन लोगों को दिया जाना था जो स्वेच्छा से आगे आए थे और आपातकाल की उद्घोषणा की अवधि के दौरान नामांकित या कमीशन किए गए थे, न कि पहले या बाद में। हालाँकि, मामला कठिनाई से मुक्त नहीं था और इंद्राज सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य<sup>1</sup>, मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। इसमें प्रतिवादी-राज्य की ओर से कड़ा रुख अपनाया गया कि याचिकाकर्ता लाभ का हकदार नहीं था क्योंकि वह आपातकाल की घोषणा से पहले सैन्य सेवा में शामिल हो गया था। हालाँकि, प्रतिवादी-राज्य के इस रुख को स्वीकार नहीं किया गया और न्यायमूर्ति ए.एस. बैंस ने फैसला सुनाया कि मौजूदा नियमों के तहत लाभ उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध था, जिन्होंने आपातकाल की अवधि के दौरान सैन्य सेवा प्रदान की थी, चाहे वे आपातकाल की उद्घोषणा के लिए पहले नामांकित हों या आपातकाल की अवधि के दौरान। जाहिर तौर पर इस फैसले के कारण, 4 अगस्त, 1976 को प्रतिवादी हरियाणा राज्य ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) हरियाणा दूसरा संशोधन नियम, 1976 लागू किया। इस प्रकार प्रतिवादी-राज्य के इरादे को प्रभावी करने के लिए मौजूदा नियमों में नियम 2 की परिभाषा को पूरी तरह से प्रतिस्थापित किया गया था कि सैन्य सेवा का लाभ उन व्यक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए जो ऑपरेशन की अवधि के दौरान नामांकित या कमीशन किए गए थे। आपातकाल और दूसरों के लिए नहीं। यह संशोधन 1 नवंबर, 1966 को लागू हुआ माना गया।

<sup>1</sup> (1979) 3 अस आल आर 441

(5) नियम 2 में सैन्य सेवा की परिभाषा को पूर्ववर्ती पंजाब नियमों में मौजूद और हरियाणा संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित की गई परिभाषा के साथ तुलना करना शिक्षा प्रद इस प्रकार है: -

### पंजाब

2. परिभाषा.-इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति 'सैन्य सेवा' का अर्थ है भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों में से किसी में नामांकित या कमीशन की गई सेवा (जिसमें वारंट अधिकारी के रूप में सेवा भी शामिल है) जो किसी व्यक्ति द्वारा अवधि के दौरान प्रदान की गई हो। 26 अक्टूबर, 1962 को संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की उद्घोषणा का संचालन, या ऐसी अन्य सेवा जिसे इसके बाद इन नियमों के प्रयोजनों के लिए सैन्य सेवा के रूप में घोषित किया जा सकता है। सैन्य सेवा के बाद सैन्य प्रशिक्षण की किसी भी अवधि को भी सैन्य सेवा के रूप में गिना जाएगा।

### हरियाणा

इन नियमों के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति 'सैन्य सेवा' का अर्थ सीएल व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवा है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की उद्घोषणा के संचालन की अवधि के दौरान नामांकित या कमीशन किया गया था। 26 अक्टूबर, 1962, उक्त आपातकाल की अवधि के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के तीन विंगों में से किसी एक में (वारंट अधिकारी के रूप में सेवा सहित) या ऐसी अन्य सेवा जिसे इसके बाद इन नियमों के प्रयोजन के लिए सैन्य सेवा के रूप में घोषित किया जा सकता है। सैन्य प्रशिक्षण के बाद सैन्य सेवा की किसी भी अवधि को भी सैन्य सेवा के रूप में गिना जाएगा।

यह स्पष्ट है कि यहां प्रश्न का मूल यह है कि क्या प्रतिवादी राज्य हरियाणा के पास नियमों में सैन्य सेवा की परिभाषा को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करने की शक्ति है (जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है) और यदि हां, तो क्या उस शक्ति का वास्तविक प्रयोग असंवैधानिकता का दोष से प्रभावित होता है। तथ्यात्मक रूप से यह देखा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति ने 26 अक्टूबर, 1962 को संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी, जो 10 जनवरी, 1968 तक चली।

6. याचिकाकर्ता की ओर से हमले का खामियाजा सबसे पहले पंजाब सरकार द्वारा प्रतिस्थापित नियम 2 को दी गई पूर्वव्यापीता के खिलाफ निर्देशित किया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) हरियाणा दूसरा संशोधन नियम, 1976, इसकी मांग की गई थी। (इसके बाद हरियाणा संशोधन नियम कहा जाएगा) तर्क दिया जा सकता है कि पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम 1965 (बाद में इसे पंजाब नियम कहा

जाएगा) में सैन्य सेवा की पूर्व परिभाषा याचिकाकर्ता और उन सभी लोगों को एक निहित अधिकार देती है जिन्होंने आपातकाल की अवधि के दौरान सेवाओं में सेवा की थी। अब संभवतः किसी भी तरह से उनसे छीना नहीं जा सकता है। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता और वर्ग के अन्य लोग एक बार पंजाब नियमों के आधार पर दिए गए लाभ के हकदार बन गए थे, उन्हें उसी नियमों के बाद के संशोधन द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता है पूर्वव्यापी प्रभाव से। संक्षेप में, यह रुख था कि चूंकि पहले पंजाब नियमों के तहत याचिकाकर्ता को जो रियायत उपलब्ध कराई गई थी, उसे अब हरियाणा संशोधन नियमों द्वारा छीनने की मांग की गई है, इसलिए, केवल इस आधार पर उत्तरार्द्ध भारत के संविधान के 14 और 16 अनुच्छेदों का उल्लंघन है।

(7) मैं उपरोक्त तर्क की सराहना करने में असमर्थ हूं, बावजूद इसके कि इसे जिस जोर-शोर से दबाने की कोशिश की गई थी। यदि विधायिका या नियम-निर्माता प्राधिकारी के पास पूर्वव्यापी अधिनियम बनाने की पूर्ण शक्ति है तो यह अनिवार्य रूप से इसका पालन करेगा कि उसके पास पहले से प्रदत्त लाभ या अधिकार को छीनने की शक्ति है। वर्तमान मामले में, यह विशेष रूप से उजागर करने योग्य है कि याचिकाकर्ता का वेतन वृद्धि, वरिष्ठता, पेंशन, आदि, या उसके द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा से आवश्यक रूप से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों का दावा किसी अंतर्निहित या मौलिक अधिकार से प्राप्त नहीं है, बल्कि स्वयं मात्र है पहले के पंजाब नियमों का प्राणी, जिसने एक सीमित वर्ग को यह रियायत या लाभ प्रदान करने का विकल्प चुना था। पंजाब नियमों के प्रावधान पर एक स्पष्ट नज़र डालने से पता चलेगा कि पहले की सैन्य सेवा के लिए वेतन वृद्धि, वरिष्ठता और पेंशन आदि के ये विशेष लाभ उन्हें दी गई रियायत की प्रकृति में हैं। याचिकाकर्ता या उसके जैसे अन्य लोगों के पास स्पष्ट रूप से कोई पूर्व कानूनी अधिकार या अंतर्निहित दावा नहीं हो सकता है। न केवल ऐसा है, बल्कि नियम स्वयं भी यही कहते हैं और वास्तव में उनके शीर्षक में ही इसे इस तरह स्टाइल किया गया था (यानी, रियायत)। इसलिए वही प्राधिकारी जिसने रियायत प्रदान की थी, वह उस रियायत को वापस लेने या बदलने का समान रूप से हकदार होगा यदि उसके पास पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति हो। इसलिए, मामला दोहरे पहलू पर आ जाएगा। सबसे पहले, क्या प्रतिवादी-हरियाणा राज्य के पास नियमों को वैध रूप से पूर्वप्रभावीता देने की शक्ति है? यदि हां, तो क्या इस तरह की पूर्वव्यापी कार्रवाई द्वारा पिछली रियायत को छीनना आवश्यक रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन होगा।

8. इसमें किसी भी प्रकार का संदेह प्रतीत नहीं होता है कि प्रतिवादी-हरियाणा राज्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत पूर्वव्यापी रूप से नियम बनाने की पूर्ण शक्ति है जब तक कि विधायिका अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के संबंध में एक अधिनियम नहीं बनाती है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अब तक इस बिंदु



पर विधायिका का कोई अधिनियम नहीं है और परिणामस्वरूप प्रतिवादी-राज्य वस्तुतः विधायिका के स्थान पर कदम रखता है और उसके पास पूर्वव्यापी रूप से नियम बनाने की पूर्ण शक्ति है। प्रथम दृष्टया हरियाणा नियम यह घोषित करते हैं कि इन्हें अनुच्छेद 309 के परंतुक से प्राप्त शक्ति के तहत तैयार किया जा रहा है। 'इस प्रकार, यह मामला सैद्धांतिक रूप से विस्तार और इसमें संदर्भ के लायक नहीं लगता है। एक कनेक्शन पहले बी अस वडेरा बनाम भारत संघ और अन्य<sup>2</sup>, हो सकता है, जिसमें इसे इस प्रकार निर्धारित किया गया था: -

"\* \* \* नियम, जिन्हें संविधान के प्रावधानों के अधीन होना है, ऐसे किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रभावी होंगे। यानी, यदि उपयुक्त विधानमंडल ने अनुच्छेद 309 के तहत एक अधिनियम पारित किया है, तो नियम परंतुक के तहत बनाए गए, उस अधिनियम के अधीन प्रभावी होंगे, लेकिन, उपयुक्त विधानमंडल के किसी भी अधिनियम की अनुपस्थिति में, इस मामले पर, हमारी राय में, राष्ट्रपति या उनके जैसे व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियम निर्देशित कर सकते हैं, संभावित और पूर्वव्यापी दोनों तरह से पूर्ण प्रभाव डालेंगे।"

उपरोक्त दृष्टिकोण को कभी भी खारिज नहीं किया गया है और वास्तव में उसी की एक हालिया पुनरावृत्ति राज कुमार बनाम भारत संघ आदि<sup>3</sup> में निम्नलिखित शब्दों में दिखाई देती है।

"\* \* \* इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह नियम एक वैध नियम है क्योंकि अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियम विधायी हैं और इसलिए, इन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जा सकता है।"

वास्तव में मामले के इस पहलू को याचिकाकर्ताओं की ओर से स्पष्ट रूप से किसी गंभीर चुनौती के तहत नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से माना जाना चाहिए कि प्रतिवादी-हरियाणा राज्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत पूर्वव्यापी प्रभाव से नियम बनाने का अधिकार था और उसने हरियाणा संशोधन नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसा किया है।

9. एक बार ऐसा होने पर, अगला मुद्दा यह उठता है कि क्या नियमों के समान सेट के हरियाणा संशोधन द्वारा पंजाब नियमों द्वारा पहले दी गई रियायत को वापस लेना अनिवार्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन होगा। मेरे विचार से, यह फिर से केवल नकारात्मक उत्तर को ही स्वीकार करता है। यह प्राथमिक

<sup>2</sup> ए आई आर 1969 अस सी 118

<sup>3</sup> ए आई आर 1975 अस सी 1116

प्रतीत होता है कि किसी भी कानून का पूर्वव्यापी प्रभाव अनिवार्य रूप से पहले से मौजूद अधिकारों को प्रभावित या परिवर्तित करना चाहिए। केवल इसलिए कि वे ऐसा करते हैं, पूर्वव्यापी कानून को समानता नियम का उल्लंघन करने वाला घोषित नहीं किया जा सकता है। ऐसा मानने का वास्तव में अर्थ यह होगा कि पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की कोई वैध शक्ति कभी नहीं हो सकती। सैद्धांतिक तौर पर मुझे इस प्रश्न पर थोड़ा संदेह है, लेकिन अंतिम न्यायालय के प्राधिकारियों के पास इस मुद्दे पर कोई कमी नहीं है। इस संबंध में कालानुक्रमिक संदर्भ सबसे पहले एमएसटी को दिया जा सकता है। रफीग्यू-नेसा, आदि बनाम लाई बहादुर छेत्री<sup>4</sup>, इसमें न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या पूर्वव्यापी कानून द्वारा निहित स्वामित्व अधिकार को भी छीना जा सकता है या बदला जा सकता है। इसे इस प्रकार देखा गया:-

“\* \* \* यह उनके लिए विवादित नहीं है कि विधायिका पूर्वव्यापी कानून के माध्यम से निहित अधिकारों को छीनने में सक्षम है। इसी तरह, विधायिका निस्संदेह ऐसे कानून बनाने में सक्षम है जो पार्टियों के बीच अनुबंध की शर्तों को ओवरराइड और भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं; लेकिन तर्क यह है कि जब तक विधायिका द्वारा उस संबंध में उपयुक्त व्यक्त शब्दों को अपनाकर एक स्पष्ट इरादे का संकेत नहीं दिया जाता है, तब तक किसी कानून के प्रावधान को पूर्वव्यापी संचालन नहीं दिया जाना चाहिए, यदि इस तरह के संचालन से निहित अधिकार प्रभावित होने की संभावना हो। ये सिद्धांत अपवादहीन हैं और कानून के तौर पर इन पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती।”

उपरोक्त दृष्टिकोण को राज कुमार के मामले (सुप्रा) में माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. अलागिरीस्वामी द्वारा अलग-अलग शब्दों में इस प्रकार दोहराया गया है: -

“\* \* \* एक बार जब किसी कानून को किसी विशेष तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाता है, तो संशोधन किए जाने से पहले भी अधिनियम के तहत की गई सभी कार्रवाइयों को संशोधित अधिनियम के तहत लिया गया माना जाएगा और वास्तव में ऐसा करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। पहले से की गई किसी भी कार्रवाई को मान्य करें, बशर्ते कि यह उस तारीख के बाद की हो, जब से संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है।”

अंत में इस बिंदु पर राम फल सिंह और आदि बनाम हरियाणा राज्य और आदि<sup>5</sup> मामले में माननीय न्यायमूर्ति आर.एन. मित्रल की टिप्पणियाँ हैं, जिसमें एक नियम के पूर्वव्यापी संचालन के आधार पर एक पूर्व राष्ट्रपति आदेश को रद्द कर दिया गया था और इसे

<sup>4</sup> 1964 अस सी 1511

<sup>5</sup> सी डब्लू 3281/77 निर्धारित किया गया दिनांक 11 अक्टोबर 1979

परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की सेवा के नियमितीकरण आदि सहित बनाए गए सेवा अधिकारों को शून्य कर दिया गया। ऐसे पूर्वव्यापी कानून की वैधता को कायम रखते हुए सिद्धांत और अधिकारियों के विचार के बाद निम्नानुसार देखा गया: -

“\* \* \*उपरोक्त चर्चा से, यह उभर कर आता है कि एक पूर्वव्यापी कानून वह है जो पीछे की ओर भी देखता है, यह मौजूदा कानून के तहत प्राप्त निहित अधिकारों को छीन लेता है या खराब कर देता है। किसी कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव देने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है यदि वह निहित अधिकारों को नहीं छीन सकता। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि पूर्वव्यापी कानून खराब है क्योंकि यह किसी व्यक्ति को कुछ निहित अधिकारों से वंचित करता है।

मेरे विद्वान भाई न्यायमूर्ति जी.सी.मित्तल, इस विचार से सहमत प्रतीत होते हैं कि पंजाब नियमों को केवल रियायत देने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि एक अधिकार प्रदान करना है जिसे कानून की अदालत में लागू किया जा सकता है। तर्कों के लिए यह मान भी लिया जाए कि ऐसा था, तो इससे स्पष्ट रूप से किसी कानूनी अधिकार को छीनने की पूर्वव्यापी शक्ति की संवैधानिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही यह माना जाए कि पंजाब नियमों ने याचिकाकर्ता को लागू करने योग्य अधिकार प्रदान किए थे, उन्हें उसी प्राधिकारी द्वारा छीना जा सकता है जिसने पहले उन्हें प्रदान किया था यदि उसके पास पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति है। यहां प्रतिवादी-राज्य की नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने की क्षमता संदेह में नहीं है और इसलिए, चाहे पहले दिया गया अधिकार वैधानिक रियायत की प्रकृति में था या कानून की अदालत में लागू करने योग्य अधिकार था, उसे बदला या नष्ट किया जा सकता है एक वैध आगामी विधान द्वारा।

10. इस पहलू पर निष्कर्ष निकालने के लिए यह माना जाना चाहिए कि प्रतिवादी-हरियाणा राज्य के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियमों को पूर्वव्यापी रूप से अधिनियमित करने की पूर्ण शक्ति है, जो नियमों के समान सेट द्वारा पहले दी गई किसी भी रियायत को अनिवार्य रूप से छीन सकता है। किसी भी तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता नियम का उल्लंघन या उल्लंघन किए बिना।

11. वर्गीकरण की वैधता के बिंदु पर मुख्य तर्क पर ध्यान देने से पहले, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को निष्पक्षता में, उसकी ओर से उठाए गए दो तर्कों पर संक्षेप में ध्यान देना आवश्यक लगता है। वकील ने यहां तक तर्क दिया कि न तो किसी वैधानिक नियम के द्वारा और न ही अधिनियम के द्वारा, केवल 1962 में आपातकाल की घोषणा के बाद सेवा में शामिल होने वालों को रियायत दी जा सकती है और यदि दी जानी चाहिए तो तीनों लड़ने वाली सेवाएँ के सभी सदस्यों को दी जानी चाहिए। वास्तव में उन्होंने तर्क

दिया कि यदि इस तरह की रियायत सेवाओं के पूरे एक विंग, अर्थात् केवल सेना तक ही सीमित थी, तो उसे भी भेदभावपूर्ण माना जाना चाहिए। उनके अनुसार, इस तरह की रियायत के दायरे में थल सेना, नौसेना और वायु सेना के तीनों अंगों को आना चाहिए। हालाँकि, इन तर्कों को बेधड़क तरीके से पेश करने के अलावा, इसके समर्थन में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया जा सका। मामले को विस्तार से बताने के लिए बेंच द्वारा बार-बार दबाव डालने के बावजूद, वकील केवल पूर्वोक्त कथित सिद्धांतों को दोहराने से संतुष्ट रहे और चूंकि ये मुझे न तो सैद्धांतिक रूप से समर्थित प्रतीत होते हैं, और न ही इसके समर्थन में किसी प्राधिकारी का हवाला दिया जा सकता है, इसलिए ऐसे में इसे हाथ से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

12. अनिवार्य रूप से, उपरोक्त हठधर्मिता के परिणाम के रूप में कि तीनों सेवाओं के सभी और प्रत्येक सदस्य को रियायत दी जानी चाहिए, तब याचिकाकर्ताओं की ओर से यह आग्रह किया गया था कि उन व्यक्तियों का वर्गीकरण किया जाए जो भर्ती के दौरान नामांकित या कमीशन किए गए थे। आपातकाल की उद्घोषणा का संचालन उचित नहीं था और इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन था। इस मुख्य तर्क का वैकल्पिक अंग यह था कि भले ही युद्ध की स्थिति में सैन्य सेवा का चयन करने वाले स्वयंसेवकों का एक अलग और स्पष्ट वर्ग हो, फिर भी इस वर्ग को रियायत देने का नियमों द्वारा प्राप्त किया गया इच्छित उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं होगा। मामला यह था कि जिन लोगों को आपातकाल से पहले नामांकित किया गया था, और वे लोग जिन्होंने इसके संचालन के दौरान स्वेच्छा से काम किया था, वे इतने सुगठित और अविभाज्य वर्ग थे कि रियायत देने के लिए एक को दूसरे से अलग करना पूरी तरह से मनमाना होगा और फलस्वरूप असंवैधानिक होगा।

13. अब उपरोक्त तर्क का बारीकी से विश्लेषण, जो मुझे काफी लंबा लगता है, इसकी भ्रांति के विभिन्न पहलुओं को सामने लाएगा। जैसा कि पहले कहा गया है, मूल रूप से 1965 में बनाए गए पूरे पंजाब नियमों की योजना और निकाय की जांच से संकेत मिलता है कि ये स्पष्ट रूप से उन लोगों को सरकार द्वारा दी गई रियायत की प्रकृति में हैं जिन्होंने उसके विचार में आपातकाल के दौरान देश सेवा प्रदान की थी। इन नियमों से पहले, वेतन वृद्धि, पेंशन, वरिष्ठता या पदोन्नति आदि के संबंध में ऐसे कोई लाभ उन पुरुषों को उपलब्ध नहीं थे, जिन्होंने सैन्य सेवा प्रदान की हो। यह ध्यान में रखना होगा कि उस समय तक आपातकाल लगभग तीन वर्षों से लागू था। ऐसा नहीं है कि जब भी कोई सैनिक सिविल रोजगार में स्थानांतरित होता है तो इन लाभों का दावा करने के लिए उसके पास पहले से ही कोई मौलिक या अंतर्निहित अधिकार मौजूद था। इसलिए, प्रतिवादी-राज्य किसी विशेष वर्ग को ये लाभ प्रदान कर सकता है और किसी अन्य वर्ग के बहिष्कार को न तो भेदभावपूर्ण माना जा सकता है और न ही निहित अधिकार छीनने

वाला माना जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है और स्पष्ट रूप से यह मानना होगा कि मूल रूप से प्रतिवादी-राज्य ने सैन्य सेवा के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार दोनों के रूप में अपने इनाम में ये रियायतें या लाभ दिए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरी तरह से तय हो चुका है कि मूल रूप से रियायत देते समय, उसके लाभार्थी को चुनना राज्य का काम है, और जहां इसे व्यक्तियों के एक बड़े समूह तक विस्तारित करने की मांग की जाती है, तभी शायद उनके अस्तित्व पर विचार किया जाएगा। एक पहचान योग्य वर्ग उत्पन्न हो सकता है। ऐसा होने पर, इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या युद्ध या आपातकाल की स्थिति में नामांकन करने वाले या कमीशन मांगने वाले व्यक्ति उन लोगों से अलग वर्ग हैं जिन्हें पेशेवर करियरवादी कहा जा सकता है या वे लोग जो शांति के समय में रोजगार के रूप में सेवा में शामिल होते हैं।

14. मुझे यह बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति आपातकाल की घोषणा और उसके परिणामस्वरूप युद्ध के आसन्न खतरे के दौरान स्वेच्छा से नामांकन करने या कमीशन लेने के लिए आगे आते हैं, वे अपने आप में एक वर्ग बना लेंगे। यह स्वयंसिद्ध है कि युद्ध से उत्पन्न होने वाले घातक खतरे के सामने, कई लोग इसके खतरों को लेने में संकोच करेंगे। वास्तव में यह बहुत प्रसिद्ध है और थोड़ा विस्तार से कहने योग्य है कि शांति के समय में कई राज्यों में भर्ती करने वालों की कोई कमी नहीं होती है, युद्ध के समय में संबंधित व्यक्तियों की इच्छा के विरुद्ध भी भर्ती या मर्दानगी का मसौदा तैयार करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए, उन व्यक्तियों का वर्ग जो अपने सभी घातक खतरों के साथ युद्ध सेवा के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं (और कई बार अनिश्चितता की शर्तों पर, यदि रोजगार आकर्षक से दूर है) निस्संदेह पेशेवर सेवा कैरियरवादियों से अलग और भिन्न हैं। पिथिली, यह एक ऐसा वर्ग है जो युद्ध के समय हथियारों के आह्वान का देशभक्तिपूर्वक जवाब देता है, उन लोगों के विरुद्ध जो शांति में पेशेवर रूप से सेवाओं में रोजगार की तलाश कर सकते हैं। यह किसी भी तरह से उन लोगों का अपमान नहीं है जो शांति के समय में सेवाओं में शामिल होते हैं और समान रूप से सम्मानजनक भूमिका निभाते हैं, लेकिन निस्संदेह उन लोगों से अलग है जो आपातकाल के पेटेंट और कभी-कभी घातक खतरों का सामना करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। समान रूप से यह देखा जा सकता है कि जो लोग शांति के समय में सेवाओं में शामिल हुए हैं, वे युद्ध के दौरान स्वेच्छा से या अनिच्छा से सेवा करने के लिए बाध्य हैं। हालाँकि, पुरुषों का एक अन्य वर्ग भी है जो इस तरह के किसी दायित्व के अधीन नहीं है, लेकिन युद्ध के खतरे के सामने आने पर भी स्वेच्छा से आगे आते हैं और ऐसे समय में जब देश को उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। इसे और अधिक सटीक रूप से कहें तो, जो व्यक्ति आपातकाल की घोषणा से पहले सेवाओं में शामिल होते हैं, वे स्पष्ट रूप से पेशेवर सैनिक और नियमित सेवा कैरियर के दायरे में आते हैं, उन लोगों के विपरीत जो युद्ध की स्थिति में आपातकाल के दौरान स्वेच्छा से नामांकन करने या

कमीशन लेने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए, किसी भी कोण से देखने पर, इस तथ्य से कोई बच नहीं सकता है कि जो व्यक्ति किसी आपात स्थिति के दौरान स्वेच्छा से सैन्य सेवा के लिए स्वेच्छा से भाग लेते हैं, उन्हें अपने आप में एक वर्ग के रूप में माना जा सकता है और वास्तव में ऐसा किया जाना चाहिए। आक्रमण योग्य होने से दूर, अनुचित होने के कारण, यह वर्गीकरण वास्तव में मुझे सबसे स्वाभाविक लगता है।

15. फिर से नियमों द्वारा प्रदत्त रियायतों और लाभों को आपातकाल में सेवा देने वाले सभी और प्रत्येक रक्षा कर्मियों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटे वर्ग तक सीमित रखने की तर्कसंगतता स्वयं स्पष्ट प्रतीत होती है। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह सही तर्क दिया गया था कि भारत की संपूर्ण रक्षा सेवाओं को ये रियायतें देना, जिनकी संख्या लाखों में है, स्वयं अनुत्पादक हो सकती है और स्वयंसेवकों को आमंत्रित करने के प्रतिवादी-राज्य के पेटेंट उद्देश्य को विफल कर देगी। खतरे के समय में या कर्तव्य के आह्वान का उत्तर देने के लिए उन्हें समान रूप से पुरस्कृत करना। इसलिए, प्रतिवादी-राज्य की इच्छा इन लाभों को कम संख्या तक सीमित करने और उन अकेले लोगों पर ध्यान केंद्रित करने की है जो देश के लिए स्पष्ट खतरे के समय स्वेच्छा से आगे आते हैं, और कई बार किसी भी कैरियर प्रेरणा के बावजूद, ऐसा प्रतीत होता है तर्कसंगत और प्रशंसनीय दोनों। इसलिए, वर्गीकरण को छोटा करना स्पष्ट रूप से तर्कसंगतता के विचारों पर आधारित है।

16. इस संदर्भ में एक बार फिर इस तथ्य को विचार से बाहर नहीं किया जा सकता है कि इन रियायतों को प्रदान करने से अनिवार्य रूप से उन लोगों के अधिकार पर आघात होगा जो सिविल सेवा के नियमित और सामान्य सदस्य हैं, जिसमें रिहा किए गए सेवा कर्मी शामिल हो सकते हैं। सैन्य सेवा को पुरस्कृत करते समय, नियमित सिविल सेवा के वैध हितों को देखना भी प्रतिवादी-राज्य का समान रूप से कर्तव्य होगा, जिन्होंने पहले उन विभागों में सेवा की थी और अपनी वरिष्ठता, पदोन्नति के अधिकारों आदि के निरंतर अस्तित्व को मानने के हकदार थे। इन सिविल सेवाओं में शामिल होने वाले रिहा किए गए सैन्य कर्मियों को वरिष्ठता, पदोन्नति आदि के मुद्दे पर रियायत मिलती है, जो उनके पक्ष में सैन्य सेवा के लिए अंतर्निहित वेटेज लाता है, निस्संदेह सिविल सेवाओं के मौजूदा सदस्यों के अधिकारों और संभावनाओं पर प्रभाव डालता है। इसलिए, प्रतिवादी-राज्य उस वर्ग को सीमित करना चाह सकता है, जिस पर सिविल सेवाओं के नियमित मौजूदा पदधारियों की तुलना में ये विशिष्ट लाभ और रियायतें प्रदान की जानी हैं। इसलिए, तर्क की मांग है कि रियायत विवेक के चारों कोनों के भीतर दी जानी चाहिए ताकि युद्ध के समय आगे आने वाले स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित किया जा सके और साथ ही सिविल सेवा के सामान्य नियमित सदस्यों को अत्यधिक हतोत्साहित या हतोत्साहित न किया जाए, जो शायद नहीं आपातकाल के दौरान ऐसी युद्ध सेवा प्रदान करने का अवसर या

योग्यता हो। इस दृष्टिकोण से भी, प्रतिवादी-राज्य तर्कसंगत रूप से पूर्व-सैनिकों के पक्ष में रियायतों के अनुदान को युद्ध के समय में इच्छुक स्वयंसेवकों के सीमित वर्ग तक सीमित करना चाह सकता है, जो कि सैनिक पेशेवर के पूरे दायरे के विपरीत है। इसलिए, एक तरफ सैन्य सेवा के प्रतिद्वंद्वी हितों और दूसरी तरफ सिविल सेवा के मौजूदा पदाधिकारियों के अधिकारों से दूर रहने की प्रतिवादी-राज्य की इस प्रशंसनीय इच्छा के चक्र में कोई भी बात डालने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि रियायतों को एक छोटे वर्ग तक सीमित करने का प्रयास तर्कसंगतता के स्पष्ट विचारों पर आधारित है और संभवतः इसे मनमाना या अनुचित नहीं माना जा सकता है।

17. अब नियमों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य की बात करें तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक दोहरा उद्देश्य इसके मूल में है। यह स्पष्ट रूप से नागरिकों को युद्ध के समय में आगे आने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है जब देश में सेवा कर्मियों की आवश्यकता सबसे अधिक है और इन इच्छुक स्वयंसेवकों को समान रूप से पुरस्कृत करना है और यह स्पष्ट करना है कि आपातकाल के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं बाद के जीवन में जब वे राज्य के अधीन सामान्य नागरिक रोजगार में लौटते हैं तो उन्हें न तो भुलाया जाएगा और न ही खोया जाएगा। जैसा कि पहले ही देखा गया था, युद्ध के समय आगे आने में कई लोगों की शुरुआती झिझक और इस अतिरिक्त खतरे को दूर करना होगा कि सेना में प्रदान की गई सेवा अस्थायी हो सकती है, इस पर काबू पाना होगा। इस प्रकार नियमों का उद्देश्य इन दो पंक्तियों पर निर्देशित था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य द्वारा अपनाए गए संकीर्ण वर्गीकरण (आपातकाल के दौरान सेवारत संपूर्ण रक्षा सेवाओं तक इसे विस्तारित करने के विपरीत) का नियमों के उद्देश्य से स्पष्ट संबंध है।

18. मेरे विद्वान भाई न्यायमूर्ति मितल, के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, मैं उनके इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि आपातकाल के दौरान सेवा प्रदान करने वाली रक्षा सेवाओं का पूरा दायरा इतना अविभाज्य वर्ग है कि इसे संविधान के तहत अनुमति है सीमित या सीमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समान रूप से, यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ता देई चंद की प्रारंभिक नियुक्ति या उसकी वैधता पर सवाल नहीं उठाया गया या उसे मुद्दे में नहीं डाला गया। रिट याचिका में एकमात्र दावा वरिष्ठता, पेंशन, पदोन्नति आदि के दावे के संबंध में था, इस आधार पर कि वह अब सेवा में पक्का हो गया है। सम्मान के साथ, ऐसे किसी भी काल्पनिक विचार, जो कभी मुद्दे में नहीं थे, हरियाणा संशोधन की संवैधानिकता या अन्यथा व्याख्या करने में बहुत कम प्रासंगिक हो सकते हैं। जाहिर है, कई याचिकाकर्ताओं में से किसी एक के मामले के व्यक्तिगत तथ्य बहुत कम या बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं। मेरे विचार से, ये सहायक और

निर्णायक कारक, हरियाणा संशोधन को उसकी संवैधानिकता के लिए अनुच्छेद 14 और 16 की कसौटी पर परखने के लिए सार्थक विचार नहीं हो सकते हैं।

19. यहां जो बात और उजागर करने लायक है वह यह है कि नियमों के तहत रियायतें और लाभ प्रदान करने के लिए सीमित वर्ग पर हमला करने में याचिकाकर्ता की ओर से कम से कम अनुचित मकसद या गुप्त विचार का भी सुझाव नहीं दिया गया है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, वर्गीकरण को सीमित और संकीर्ण करने की इच्छा तार्किक और उचित विचारों पर आधारित है। शुरुआत में यह देखा गया कि प्रतिवादी-राज्य का रुख यह है कि शुरू से ही उसका इरादा इस सीमित वर्ग को लाभ प्रदान करना था, लेकिन जाहिर तौर पर ड्राफ्ट्समैन परिणाम के साथ उस इरादे को सटीक भाषा में अनुवाद करने में असमर्थ था। यह इतना विस्तृत था कि इसमें आपातकाल के दौरान और उससे पहले नामांकित लोगों दोनों को शामिल किया जा सके। यह याद रखने योग्य है कि पहले भी इंद्राज सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-राज्य का रुख यह था कि रियायतें केवल उन लोगों तक ही सीमित थीं जो आपातकाल के दौरान सैन्य सेवा में शामिल हुए थे और उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने पहले ऐसा किया था। जब अदालत का फैसला प्रतिवादी-राज्य के खिलाफ गया, तो उसने पंजाब नियमों में संशोधन करके अपना इरादा स्पष्ट करने की वैध प्रक्रिया का सहारा लिया। यह कहना इस न्यायालय का काम नहीं है कि प्रतिवादी-राज्य को अब रियायतों को एक सीमित वर्ग तक सीमित रखने के अपने स्पष्ट इरादे को लागू करने से हमेशा के लिए रोक दिया गया है।

20. एक बार जब यह माना जाता है कि नियमों का उद्देश्य वैध और प्रशंसनीय है और वर्गीकरण एक समझदार अंतर पर आधारित है, तो यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यह अदालतों के लिए वांछनीयता पर फैसला देने का काम नहीं है वस्तु या वर्गीकरण की नींव के गणितीय मूल्यांकन में प्रवेश करना। ऐसी स्थिति में अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रतिवादी-राज्य स्पष्ट रूप से यह निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश है कि किसे लाभ और रियायतें प्रदान की जाएं। अधिकारियों की संख्या बढ़ाना अनावश्यक है। जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा और अन्य<sup>6</sup> में, संविधान पीठ के लिए बोलते हुए, माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रचूड़, ने इस प्रकार कहा: -

“इसलिए, न्यायिक जांच केवल इस बात पर विचार करने के लिए विस्तारित हो सकती है कि क्या वर्गीकरण उचित आधार पर आधारित है और क्या यह वस्तु को ध्यान में रखते हुए जुड़ा हुआ है। यह वर्गीकरण के आधार का अच्छा या गणितीय मूल्यांकन शुरू करने तक विस्तारित नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि ऐसी जांच की

<sup>6</sup> ए आई आर 1974 अस सी 1



अनुमति होती तो यह अदालतों के लिए खुला होता। वर्गीकरण की आवश्यकता या किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करने की वांछनीयता पर विधायिका या नियम बनाने वाले प्राधिकारी के निर्णय के स्थान पर अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करें।

पथुम्मा और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य<sup>7</sup>, मामले में सात न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा नियम की एक हालिया व्याख्या निम्नलिखित शब्दों में है: -

“.....यह भी स्पष्ट है कि वर्गीकरण करने में, विधायिका से एक अमूर्त समरूपता प्रदान करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन वर्गों को अनुभव और आसपास की परिस्थितियों के अनुसार समाज की आवश्यकताओं और अनिवार्यताओं के अनुसार अलग करना होगा। बस इतना ही आवश्यक है कि वर्गीकरण मनमाना, कृत्रिम या भ्रामक न हो.....

21. निष्कर्ष निकालने के लिए, मेरा विचार है कि जो स्वयंसेवक युद्ध के समय और आपातकाल के समय सैन्य सेवा प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, वे एक अलग वर्ग बनाते हैं और प्रतिवादी-राज्य लाभ प्रदान करने के अपने अधिकारों के भीतर पूरी तरह से था और इस सीमित वर्ग को वैधानिक नियमों की रियायतें। वर्गीकरण स्पष्ट रूप से समझने योग्य अंतर पर आधारित है और नियमों द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु और उद्देश्य के साथ इसका सीधा संबंध है। इसलिए, हरियाणा संशोधन असंवैधानिकता के किसी भी दोष से ग्रस्त नहीं है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। अनिवार्य रूप से, सभी सिविल रिट याचिकाएं निराधार हैं और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए। हालाँकि, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाएगा।

माननीय न्यायमूर्ति श्री गुरनाम सिंह, - मैं सहमत हूँ।

माननीय न्यायमूर्ति श्री गोकल चंद, मितल,

(22) तीन रिट याचिकाओं के इस सेट में, 4 अगस्त 1976 को हरियाणा सरकार के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित पंजाब सरकार के राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) हरियाणा द्वितीय संशोधन नियम, 1976 को चुनौती दी गई है। अधिसूचना संख्या जीएसटी-182/कांस्ट./कला., 1409/प्रशासन द्वारा। (II)/76, दिनांक 4 अगस्त, 1976। मुख्य चुनौती 'सैन्य सेवा' की परिभाषा में किए गए संशोधन को लेकर है।

<sup>7</sup> ए आई आर 1978 एस सी 771

(23) इन रिट याचिकाओं पर पहले एक डिवीजन बेना द्वारा सुनवाई की गई थी और यह माना गया था कि मामला काफी महत्वपूर्ण था और एक पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय लेने योग्य था और इसी तरह से इन रिट याचिकाओं को हमारे सामने रखा गया है। संदर्भ की सुविधा के लिए, हम 1979 के सी.डब्ल्यू. संख्या 231 के तथ्यों पर गौर कर रहे हैं और यह विवादित नहीं है कि अन्य रिट याचिकाओं के तथ्य समान हैं।

(24) देई चंद याचिकाकर्ता 9 दिसंबर, 1960 को एक नियमित लड़ाकू के रूप में भारतीय वायु सेना में शामिल हुए और 15 सितंबर, 1969 तक वहां सेवा की, जब वह रिहा हुए। सैन्य सेवा के उनके कार्यकाल के दौरान, पहले अक्टूबर, 1962 में चीनी आक्रमण हुआ, और फिर 1965 का पाकिस्तानी आक्रमण हुआ। अपनी रिहाई के बाद, उन्होंने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और अन्य संबद्ध सेवाओं की एक खुली परीक्षा में भाग लिया, जो आयोजित की गई थी। 1970-71 में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा सैन्य जारी कर्मियों के लिए आरक्षित कोटा के तहत संबद्ध सेवाओं की सामान्य श्रेणी में चयनित किया गया और 22 मई, 1973 को सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी की।,—आदेश के अनुसार, अनुलग्नक पी-2।

25) जब याचिकाकर्ता उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग में शामिल हुआ, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकालीन (रियायत) नियम, 1965, अनुलग्नक पी-3, (इसके बाद पंजाब नियम के रूप में संदर्भित), लागू किए गए। लागू है और उन्होंने उपरोक्त वैधानिक नियमों के तहत वेतन वृद्धि, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि के प्रयोजनों के लिए उन्हें सैन्य सेवा लाभ देने के लिए अपने अभ्यावेदन संख्या 6029, दिनांक 2 जनवरी 1974 के माध्यम से आवेदन किया था। जबकि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व लंबित था, हरियाणा सरकार ने 4 अगस्त, 1976 को पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) हरियाणा दूसरा संशोधन नियम, 1976, अनुलग्नक पी -5 (इसके बाद हरियाणा नियम के रूप में संदर्भित) प्रकाशित किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त इसकी शक्तियों का। इन संशोधित नियमों के कारण, याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रत्यावर्तन याचिका को 15 जनवरी, 1979 के आदेश के तहत उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद अनुलग्नक पी-4 है, जो इस प्रकार है: —

“आपको सूचित किया जाता है कि चूंकि आप आपातकाल की अवधि के दौरान सेना में नामांकित नहीं थे, इसलिए, आपको सिविल सेवा के लिए सैन्य सेवा का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अतः आपके उपरोक्त अभ्यावेदन को विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया गया है।”

इसके बाद, हरियाणा के नियमों और विशेष रूप से 'सैन्य सेवा' की परिभाषा को चुनौती देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान रिट याचिका दायर की गई थी, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

(26) इस बिंदु को समझने के लिए, पंजाब नियमों और हरियाणा नियमों में निहित 'सैन्य सेवा' की परिभाषा को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा। पंजाब नियम 'सैन्य सेवा' को इस प्रकार परिभाषित करते हैं:-

"सैन्य सेवा' का अर्थ है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा के संचालन की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई भारतीय सशस्त्र बलों के तीन विंगों में से किसी में नामांकित या कमीशन सेवा (वारंट अधिकारी के रूप में सेवा सहित) 26 अक्टूबर, 1962 को संविधान के अनुसार, या ऐसी अन्य सेवा जिसे इसके बाद इन नियमों के प्रयोजनों के लिए सैन्य सेवा के रूप में घोषित किया जा सकता है। सैन्य प्रशिक्षण के बाद सैन्य सेवा की किसी भी अवधि को भी सैन्य सेवा के रूप में गिना जाएगा।

हरियाणा नियमों के तहत 'सैन्य सेवा' की परिभाषा इस प्रकार है:-

"सैन्य सेवा' का अर्थ उस व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवा है, जिसे 26 अक्टूबर, 1962 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की उद्घोषणा के संचालन की अवधि के दौरान नामांकित या नियुक्त किया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों (वारंट अधिकारी के रूप में सेवा सहित), उक्त आपातकाल की अवधि के दौरान या ऐसी अन्य सेवा जिसे इसके बाद इन नियमों के प्रयोजनों के लिए सैन्य सेवा के रूप में घोषित किया जा सकता है। सैन्य प्रशिक्षण के बाद सैन्य सेवा की किसी भी अवधि को भी सैन्य सेवा के रूप में गिना जाएगा।

यह जानना भी उपयोगी होगा कि भारत के राष्ट्रपति ने 26 अक्टूबर, 1962 को संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की, जो 10 जनवरी, 1968 तक चली। यह भी ध्यान देना उपयोगी होगा कि हरियाणा नियम, हालाँकि इन्हें 4 अगस्त, 1976 को प्रकाशित किया गया था, लेकिन इन्हें 1 नवंबर, 1966 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था।

(27) आइए अब हम 'सैन्य सेवा' की परिभाषा पर विचार करें जैसा कि यह मूल रूप से थी, इसे पढ़ने से पता चलता है कि 26 अक्टूबर, 1962 से आपातकाल की घोषणा की अवधि के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के तीन विंगों में से किसी में नामांकित सभी कमीशन अधिकारियों या कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सेवा को सैन्य के रूप में मान्यता दी जानी थी। ऐसी अन्य सेवा के अलावा सेवा जिसे नियमों के प्रयोजनों के लिए सैन्य सेवा के

रूप में घोषित किया जा सकता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए आपातकाल की घोषणा की अवधि के दौरान तीनों में से किसी भी विंग में शामिल होना आवश्यक नहीं था। वे सभी व्यक्ति जो आपातकाल की घोषणा से पहले या उसके दौरान शामिल हुए थे, इस परिभाषा के अंतर्गत आते थे और आपातकाल की घोषणा की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा को सैन्य सेवा के रूप में माना जाना था, जिसका लाभ उन्हें निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दिया जा सकता था। वेतन वृद्धि, वरिष्ठता, पेंशन, पदोन्नति आदि सैन्य सेवा के बाद सैन्य प्रशिक्षण की अवधि को भी सैन्य सेवा के रूप में मान्यता दी जानी थी। हरियाणा नियमों द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से लाई गई 'सैन्य सेवा' की परिभाषा पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि 'सैन्य सेवा' का अर्थ उस व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवा है जिसे आपातकाल की घोषणा के संचालन की अवधि के दौरान नामांकित या कमीशन किया गया था। 26 अक्टूबर, 1962 को भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों में से किसी एक का लाभ लेने के लिए। सैन्य सेवा के लिए यह आवश्यक था कि व्यक्ति को आपातकाल की घोषणा के दौरान नामांकित या कमीशन किया गया था और जो लोग आपातकाल की घोषणा से पहले शामिल हुए थे, हालांकि आपातकाल की घोषणा के दौरान सेवा की थी, वे सैन्य सेवा के लाभ के हकदार नहीं थे। आपातकाल के संचालन के दौरान वेतन वृद्धि, वरिष्ठता, पदोन्नति, पेंशन आदि के प्रयोजनों के लिए प्रदान किया गया। हालांकि, सैन्य सेवा के बाद सैन्य प्रशिक्षण की अवधि को सैन्य सेवा के रूप में मान्यता दी जानी थी। संशोधित परिभाषा का शुद्ध परिणाम यह था कि जो व्यक्ति 26 अक्टूबर, 1962 को या उसके बाद नामांकित या कमीशन किया गया था, उसे आपातकाल की घोषणा के दौरान प्रदान की गई सैन्य सेवा का लाभ मिलना था, जबकि सभी व्यक्ति जो 25 अक्टूबर को नामांकित या कमीशन हुए थे। अक्टूबर, 1962 या उस तारीख से पहले, आपातकाल की घोषणा के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा के लाभ के हकदार नहीं थे।

28) याचिकाकर्ताओं के वकील ने दृढ़तापूर्वक आग्रह किया है कि हरियाणा नियमों द्वारा 'सैन्य सेवा' की संशोधित परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है क्योंकि उन लोगों को सैन्य सेवा का लाभ देने के लिए कोई समझदार अंतर या सांठगांठ नहीं है। जिन्हें आपातकाल की घोषणा के दौरान नामांकित या नियुक्त किया गया था, उन लोगों की तुलना में जो आपातकाल की घोषणा से पहले शामिल हुए थे, लेकिन आपातकाल की घोषणा के संचालन के दौरान सेवा की थी, क्योंकि आपातकाल के दौरान सेवा करने वाले व्यक्तियों के दोनों समूह चीनी और पाकिस्तानी आक्रामकता के समान जोखिम के अधीन थे। आगे यह आग्रह किया गया है कि भेदभाव या वर्गीकरण पूरी तरह से अनुचित और मनमाना है क्योंकि इस प्रकार किए गए वर्गीकरण से कोई उद्देश्य हासिल नहीं होता है।

(29) याचिकाकर्ताओं के वकील के उपरोक्त रुख के विपरीत, राज्य की ओर से रुख यह है कि वर्गीकरण उचित है क्योंकि उन लोगों के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है जिन्होंने आपातकाल की घोषणा से पहले सैन्य सेवा को करियर के रूप में चुना था और जो लोग आपातकाल के दौरान विदेशी आक्रमण के दौरान देश की सेवा करने के लिए शामिल हुए, केवल आपातकाल की अवधि के दौरान, या तो आपातकालीन आयोग में या अल्पकालिक आयोग में। आगे यह आग्रह किया गया कि चूंकि ये केवल रियायतें थीं, इसलिए सरकार के लिए यह खुला था कि वह इसे व्यक्तियों के एक समूह को दे और दूसरे समूह को इससे इनकार कर दे और मामले को अदालत के समक्ष नहीं लाया जा सकता था।

(29-ए) पक्षों के वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि हरियाणा नियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है क्योंकि किया गया वर्गीकरण पूरी तरह से अनुचित और मनमाना है। चाहे मूल परिभाषा के तहत हो या संशोधित परिभाषा के तहत, आपातकाल की घोषणा के दौरान सैन्य सेवा में बिताई गई अवधि का लाभ दिया जाना है। यदि आपातकाल की घोषणा के दौरान सैन्य सेवा का लाभ दिया जाना है, तो हमें केवल उन लोगों को लाभ देने के लिए कोई सांठगांठ या आधार नहीं मिलता है जो आपातकाल के संचालन के दौरान नामांकित या कमीशन किए गए थे, न कि उन लोगों को जो नामांकित थे या आपातकाल की घोषणा से पहले कमीशन किया गया था लेकिन आपातकाल की अवधि के दौरान कार्य किया गया। चाहे कोई व्यक्ति आपातकाल की घोषणा से पहले सैन्य सेवा में शामिल हुआ हो या उसके जारी रहने के दौरान, सभी सैन्य सेवा के समान जोखिमों के अधीन आपातकाल की घोषणा के दौरान समान रूप से देश की सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह बहुत संभव है कि एक प्रशिक्षित सैन्य अधिकारी जो पहले शामिल हुआ हो। आपातकाल की उद्घोषणा को आक्रामकता का सामना करने के लिए मोर्चे पर भेजा जा सकता है और किसी अन्य व्यक्ति को, जो 26 अक्टूबर, 1962 को या उसके तुरंत बाद नामांकित या नियुक्त किया गया था, मोर्चे पर नहीं भेजा जा सकता है। हम इस सांठगांठ को समझ सकते हैं कि आपातकाल की घोषणा के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों में से किसी एक में सेवा करने वालों को नियमों के तहत लाभ मिलेगा, लेकिन 26 अक्टूबर, 1962 से पहले शामिल होने वालों को नियमों के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। अंतर के लिए कोई उचित तर्क, सांठगांठ या आधार नहीं बताया गया है, सिवाय इसके कि जो लोग आपातकाल की घोषणा के दौरान सैन्य सेवा में शामिल हुए थे, वे खुली आंखों के साथ आए थे कि उन्हें विदेशी आक्रमण के दौरान जीवन के सभी जोखिमों के साथ देश की सेवा करनी होगी और वे व्यक्ति या तो आपातकालीन आयोग या अल्पकालिक आयोग में शामिल हो गए। हम आपातकालीन आयोग या अल्पकालिक आयोग के आधार पर बताए गए भेदभाव से प्रभावित नहीं हैं। हमारे सामने यह विवादित नहीं था कि आपातकाल के दौरान भी, आपातकालीन आयोग और अल्पकालिक आयोग

में नामांकन के अलावा नियमित कमीशन अधिकारियों को भी नामांकित किया जा रहा था। यदि राज्य का यह रुख सही है कि जो लोग करियर के रूप में सेना में शामिल हुए, उन्हें इन नियमों का लाभ नहीं मिलेगा, तो उनका तर्क संशोधित परिभाषा के आधार पर ही सही बैठता है। संशोधित परिभाषा के तहत, कोई भेदभाव नहीं किया गया है कि क्या अधिकारी को नियमित आयोग, आपातकालीन आयोग या अल्पकालिक आयोग में आपातकाल के दौरान नामांकित किया गया था और संशोधित परिभाषा के तहत आपातकाल की घोषणा के दौरान प्रदान की गई सैन्य सेवा का लाभ सभी श्रेणियों के लिए स्वीकार्य है। इस तथ्य की परवाह किए बिना कि अधिकारी कैरियर के रूप में सेना में शामिल हुआ या विदेशी आक्रमण के कारण आपातकाल के कारण। इसके अलावा, जब वे नियमित कमीशन में करियर के रूप में सैन्य सेवा में शामिल होते हैं तो जीवन के लिए जोखिम से सभी परिचित होते हैं और जो लोग शॉर्ट-टर्म या आपातकालीन कमीशन में शामिल होते हैं उनके लिए जोखिम अधिक नहीं होता है, क्योंकि सभी को शांति से भी समान रूप से सेवा करनी होती है, जैसे युद्ध में।

(30) जहां तक उन अधिकारियों का संबंध है जो नामांकित हैं, वे नामांकित अधिकारियों के बीच लड़ाकू हैं, अल्पकालिक या आपातकालीन नामांकन जैसी कोई चीज नहीं है। लड़ाकू के रूप में जाने जाने वाले अधिकारियों का नामांकन हमेशा एक नियमित नियुक्ति होती है और संशोधित परिभाषा के तहत ऐसे सभी अधिकारी जो आपातकाल की घोषणा के दौरान नामांकित होते हैं, सैन्य सेवा के लाभ के हकदार हैं। यदि नामांकित अधिकारियों के बीच नियमित, आपातकालीन या अल्पकालिक जैसा कोई भेदभाव नहीं है, तो विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा का तर्क जमीन पर गिर जाता है। इसलिए, संशोधित नियम पूरी तरह से मनमाने हैं, जब वे आपातकाल के दौरान प्रदान की गई सैन्य सेवा के लाभ से केवल इसलिए वंचित कर देते हैं क्योंकि याचिकाकर्ताओं को आपातकाल की घोषणा से पहले नामांकित किया गया था, हालांकि उन्होंने आपातकाल के दौरान उसी तरह सेवा की थी जैसे आपातकाल के दौरान नामांकित अधिकारियों ने की थी। हमारे विचार से, यह एक अंतिम या लघु वर्गीकरण है जिसकी अनुमति नहीं है। आपातकाल के दौरान सेवा करने वाले व्यक्ति अपने आप में एक ऐसा वर्ग है जो आगे विभाजन करने में सक्षम नहीं है जैसा कि इस मामले में किया जाना चाहिए।

31. रिटर्न के पैरा 11 में, राज्य ने अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर हरियाणा नियम प्रकाशित होने से पहले विचार नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त किए जा रहे थे और यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर पहले निर्णय लिया गया था 4 अगस्त, 1976, यानी संशोधित नियमों के लागू होने से पहले, और भले ही उन्हें वेतन वृद्धि, वरिष्ठता आदि के प्रयोजनों के लिए पंजाब नियमों के नियम 4 के तहत सैन्य सेवा का लाभ दिया गया हो, फिर भी वे लाभ हरियाणा

नियमों के लागू होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन्हें वापस लिया जा सकता था, जिन्हें 1 नवंबर, 1966 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया था। यदि राज्य का यह रुख सही है, तो हरियाणा नियमों के कारण जो लाभ दिया गया है। याचिकाकर्ता देई चंद को पंजाब नियमों के नियम 3 के आधार पर उस अवधि के लिए आयु सीमा में छूट दी गई थी जब उन्होंने सैन्य सेवा प्रदान की थी और उन्हें उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग में नियुक्त किया गया था, इस छूट को इस परिणाम के साथ वापस लिया जाएगा कि यदि कोई लाभ नहीं मिला सैन्य सेवा में बिताई गई अवधि के लिए उन्हें सैन्य सेवा दी जाती है, तो उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति ही कानून की नजर में गलत होगी और उन्हें सेवा से बाहर करना होगा। हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार इस आधार पर उनकी सेवाएं समाप्त नहीं करेगी, लेकिन साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि, वरिष्ठता आदि का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस मामले को राज्य सरकार की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि के लाभ से वंचित करने के लिए 'सैन्य सेवा' की संशोधित परिभाषा लागू की जाए, लेकिन साथ ही इसे लागू न किया जाए। आयु सीमा में छूट देने के उद्देश्य से वह परिभाषा, जिसके तहत आपातकाल की घोषणा के दौरान सैन्य सेवा में बिताई गई अवधि के लिए आयु सीमा बढ़ा दी जाती है। हम हरियाणा नियमों के दायरे से निपट रहे हैं, जिसके आधार पर 'सैन्य सेवा' की परिभाषा में संशोधन किया गया है। यदि संशोधित नियम वैध है, तो कानून के मामले में, आवश्यक परिणाम यह होगा कि याचिकाकर्ता की उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग में प्रारंभिक नियुक्ति कानून की दृष्टि से खराब होगी।

32. हमें विद्वान महाधिवक्ता के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं मिलती कि पंजाब नियमों ने याचिकाकर्ताओं को रियायत दी है और इसे राज्य सरकार किसी भी समय वापस ले सकती है। पंजाब नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए थे, जिसका लाभ आपातकाल की घोषणा के दौरान सेना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार के रूप में उपलब्ध होगा क्योंकि एक बार वैधानिक नियम बन जाने के बाद वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। इन्हें महज रियायतें नहीं माना जाएगा बल्कि नियम बनाए गए हैं, इन्हें महज रियायतें नहीं माना जाएगा, बल्कि वैधानिक नियमों के तहत बनाया गया एक अधिकार होगा, जिसे अदालत में लागू किया जा सकता है। हालाँकि, स्लेट सरकार नियमों में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है और यदि संशोधित नियम वैध हैं, तो वे मूल नियमों का स्थान ले लेंगे, लेकिन यदि वे अमान्य हैं, तो मूल नियम बने रहेंगे। इसलिए, हमारा मानना है कि पंजाब नियमों के तहत दिया गया लाभ कोई रियायत नहीं बल्कि एक वैधानिक अधिकार था जिसे अदालत में लागू किया जा सकता था।

33. हरियाणा नियमों को 1 नवंबर, 1986 से पूर्वव्यापी बना दिया गया है, दूसरी विसंगति जो उत्पन्न होती है वह यह है कि वे सभी व्यक्ति जो भारतीय सशस्त्र बलों के तीन विंगों में

से किसी में आपातकाल की घोषणा से पहले नामांकित या कमीशन किए गए थे, लेकिन बाहर आ गए 1 नवंबर, 1966 से पहले सेवा की, आपातकाल में प्रदान की गई सैन्य सेवा के लाभ के हकदार होंगे। उन पर पंजाब नियम ही लागू होंगे। इस प्रकार भी, केवल आपातकालीन आयोग या अल्पकालिक आयोग में शामिल होने वालों को सैन्य सेवा का लाभ देने का राज्य सरकार का कथित उद्देश्य हासिल नहीं हुआ है। इसलिए, समान स्थिति वाले दो व्यक्तियों में से, जो 26 अक्टूबर, 1962 से पहले नामांकित या कमीशन किए गए थे, जो 1 नवंबर, 1966 से पहले सैन्य सेवा से मुक्त हो गए थे, उन्हें आपातकाल की घोषणा के दौरान उनकी सेवा का लाभ मिलेगा जबकि दूसरे को जो 1 नवंबर, 1966 के बाद सेना से रिहा किए गए थे, उन्हें आपातकाल की घोषणा के दौरान उनके द्वारा की गई सैन्य सेवा का लाभ नहीं मिल पाएगा। यह समान स्थिति वाले व्यक्तियों के बीच भेदभाव को भी प्रदर्शित करता है।

34. इसलिए, मामले को किसी भी कोण से देखने पर, यह पूरी तरह से स्थापित हो जाता है कि हरियाणा नियमों में निहित 'सैन्य सेवा' की परिभाषा मनमानी, अनुचित और भेदभावपूर्ण है जिसका कोई संबंध नहीं है और जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है वह हासिल नहीं किया जा रहा है और, इसलिए, यह स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है और हम इसे अमान्य घोषित करते हैं।

35. याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा हमारे सामने एक और तर्क उठाया गया कि हरियाणा नियम पूर्वव्यापी प्रकृति के कारण संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हैं। चूंकि हमने संशोधित परिभाषा को पहले से ही ऊपर दर्ज कारणों से अमान्य घोषित कर दिया है, इसलिए इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

36. ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, 1976 की सिविल रिट संख्या 5717 और 6631 और 1979 की 231 की अनुमति दी जाती है और उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, हरियाणा के आदेश, दिनांक 15 जनवरी, 1979, अनुलग्नक पी -4, सी.डब्ल्यू. में। 1979 की संख्या 231, और अन्य संबंधित रिट याचिकाओं में पारित समान आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन और मामलों पर नए सिरे से पुनर्विचार करने का निर्देश जारी किया जाता है ताकि उन्हें वेतन वृद्धि, वरिष्ठता पदोन्नति आदि, बिना कानून के अनुसार उनके लिए स्वीकार्य, के संबंध में सिविल सेवा के लिए सैन्य सेवा का लाभ दिया जा सके। हरियाणा नियमों में निहित 'सैन्य सेवा' की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए। चूंकि यह मामला लंबे समय से विचाराधीन है, इसलिए आज से तीन महीने के भीतर इसका अंतिम रूप से निपटारा हो सकता है। प्रत्येक याचिकाकर्ता अपनी लागत (प्रत्येक मामले में वकील की फीस 200 रुपये) का हकदार होगा।



### न्यायालय का आदेश.

37. बहुमत की राय के अनुसार, रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। हालाँकि, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

माननीय न्यायधीश श्री एस.एस. संधवालिया,

माननीय न्यायमूर्ति श्री गुरनाम सिंह,

माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.सी.मितल।

**अस्वीकरण** : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

संतोष (उ.ई.ड.नंबर HR0672)

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

तोशाम (भिवानी), हरियाणा

